



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124620

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19075/2026

रामबचन यादव

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

: शशांक कुमार, तेज प्रकाश यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिभुवन भारती, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 68/2026, धारा 80(2), 85, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, 1961, पुलिस थाना- जमनिया, जिला गाजीपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी मृतका का ससुर है और दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका की मृत्यु से पहले उसे प्रताड़ित करने के सामान्य आरोपों के माध्यम से उसे झूठा फंसाया गया है। दहेज की मांग और उत्पीड़न के संबंध में कोई विशिष्ट तिथि उल्लिखित नहीं है। यह भी बताया गया है कि मृतक का पति गुजरात में रहता था और निजी नौकरी करता था और उसने मृतक के खाते में पैसे का भी लेन-देन किया था, जो सह-आरोपी के खाते के विवरण से स्पष्ट है। यह भी बताया गया है कि मृतक अपने पति के साथ

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गुजरात में रहना चाहती थी, और इनकार किए जाने पर उसने आत्महत्या कर ली। यह तथ्य शव विच्छेदन से पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है। अंत में यह निवेदन किया जाता है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 9 मार्च 2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **रामबचन यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।
9. अपीलार्थी और जमानतदारों के दूरभाष संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को **गाजीपुर जेल अधीक्षक** के माध्यम से ईमेल या ई-कारागार पोर्टल द्वारा और निचली अदालत को ई-मोड द्वारा 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही **पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में **रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026** को लिया गया था।
12. कोई आवेदन यदि हो, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

2 जून, 2026

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए.के.आर.

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।